भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 462
बुधवार, 6 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

अत्यधिक विषम जलवायु

462. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती :
श्रीमती चिंता अनुराधा:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेंड्डी:
श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने इस तथ्य का कोई संज्ञान लिया है कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण तटीय आंध्र प्रदेश उन क्षेत्रों में से एक है जहां लू का प्रकोप सर्वाधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे अत्यधिक विषम जलवायु प्रभाव को कम करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई नीति बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त राज्यों को लू और इस प्रकार की स्थितियों के प्रभाव को कम करने के लिए नीतियों के कार्यान्वयन में सहायता करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) जी हां।

(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे लू समेत अत्यधिक विषम जलवायु घटनाओं के दौरान जान-माल की हानि को कम करने में सहायता मिली है। इनमें शामिल हैं:

i. तापमान एवं लू की स्थिति संबंधी मौसमी, मासिक और विस्तृत अवधि पूर्वानुमान प्रस्तुत किया जाना
ii. जिला स्तरों पर लू की स्थिति का प्रभाव आधारित पूर्वानुमान
iii. भारत में लू सुभेद्यशीलता एटलस, जिससे राज्य सरकार प्राधिकरणों एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियां को योजना बनाने तथा उचित कार्रवाई करने में सहायता मिल सके
iv. भारत में गर्म मौसम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का विश्लेषण, जिसमें दैनिक तापमान, हवा तथा आर्द्रता की स्थितियां शामिल हैं
v. समग्र देश के लिए हीट इंडेक्स पूर्वानुमान
vi. वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम लू जानकारी तथा चेतावनियां
vii. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से 23 राज्यों में संयुक्त रूप से हीट एक्शन प्लान (HAPs) क्रियान्वित किए गए
viii. सही समय पर सार्वजनिक पहुंच हेतु प्रसार प्रणालियों के आधुनिक माध्यमों का प्रयोग करते हुए चेतावनी प्रसार सेवाओं मे सुधार

(ग-घ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राज्यों को कोई वित्तीय सहायता नहीं प्रदान करता। तथापि, यह मंत्रालय देश के लिए एक समग्र रूप में "वायुमण्डल एवं जलवायु अनुसंधान-माडलिंग प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (ACROSS)" नामक सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्रियान्वित करता है, और इसलिए निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। इस स्कीम के अंग के रूप में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) मौसम, जलवायु एवं समुद्री पैरामीटर्स की निगरानी करने के लिए अत्याधुनिक प्रेक्षण प्रणलियों की तैनाती और उनका रखरखाव करता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) समाज के लाभ हेतु विभिन्न मौसमी और जलवायु सूचना, परामर्शिकाएं, चेतावनियां सृजित और प्रसारित करता है। मंत्रालय सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय लाभों हेतु मौसम, जलवायु तथा जोखिम संबंधी घटनाओं के पूर्वानुमान संबंधी क्षमताएं विकसित करने एवं उनमें सुधार करने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां निष्पादित करता है।

****